कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) से (ङ) कम साक्षरता वाले पाकेटों के अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए शैक्षिक परिसर की केन्द्रीय क्षेत्र योजना का गुजरात के कच्छ तथा बनास कांठा जिलों में कार्यान्वित किया गया । अनुसूचित जाति लड़कियों के लिए ऐसी कोई योजना गुजरात में शुरू नहीं की गई है । अनुसूचित जाति लड़कियों और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल निर्माण की केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत जिलों के चयन का निर्णय राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । इन योजनाओं के अन्य ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्र० सं०	योजना का नाम	वर्ष	प्रावधान की गई राशि (रु० लाख में)	होस्टलों/ परिसरों की संख्या	शामिल की गई लड़कियों की संख्या	लड़कियों के चयन के लिए मानदंड
1.	कम साक्षरता वाले पाकेटों में अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए शैक्षिक परिसरों की केन्द्रीय क्षेत्र योजना	1992–93	शून्य	शून्य	शून्य	योजना कार्यान्वित करने वाले स्वैच्छिक संगठन द्वारा निर्णय किया जाता है ।
		1993–94	25 327	4	200	
		1994–95	24.26	1	50	
2.	अनुसूचित जाति की लड़कियां के लिए होस्टल निर्माण की केन्द्र प्रायोजित योजना	1992–93	शून्य	शून्य	शून्य	राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया जाता है ।
		1993–94	15.06	3	150	
		1994–95	शून्य	शून्य	शून्य	
3.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल निर्माण की केन्द्र प्रायोजित योजना	1992–93	18.21	4	97	—यही—
		1993–94	19.51	3	230	
		1994–95	4.73	4	373	

अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टलों के निर्माण की योजना के अंतर्गत कुछ चुने हुए राज्यों में कुछ विख्यात अनुसंधान एजेंसियों को मूल्यांकन अध्ययनों के लिए कहा गया है । अन्य परियोनाओं का मूल्यांकन उचित समय पर किया जाएगा ।

अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित लड़कियों के शक्षिक विकास के लिए गुजरात में ऐसी कोई योजनाएं कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक विकास के लिए गुजरात में विभिन्न अन्य केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र प्रायोजित योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं जिनके अतर्गत लड़कियां भी शामिल की जाती हैं ।

अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए केन्द्रीय सहायता

5031. **श्री अजीत** पी० के० **जोगी :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार तथा अन्य राज्यों की सरकारों ने अपने अपने राज्यों में अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कोई कार्ययोजना भी प्रस्तुत की हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश को शामिल करके राज्य सरकार अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए वर्षवार आधार पर कल्याण मंत्रालय का केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत सहायता चाहते हैं । राज्य सरकारों के निष्पादन तथा राज्य सरकारों द्वारा अपने बजट में किए गए समान प्रावधानों के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं । केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत 1994–95 में की गई राज्यवार नियुक्तियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(देखिए परिशिष्ट, अनुपत्र 103)

(घ) जी, नही ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Inclusion of castes in the list of S.T. in U.P.

5032. SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the names and number of caste organisations which have requested the Central Government to include their castes in the list of S.T. in Uttar Pradesh and whose cases are pendng for decision with Government;

(b) what action Government have taken in this regard;

(c) if not, the time likely to be taken in this regard; and

(d) what is the policy and procedure adopted in such cases?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) The details are in the enclosed statement. (*See* below)

(b) and (c) All such proposals, recommendations, requests, etc. are under consideration of the Advisory Committee on Revision of Scheduled Castes/Scheduled Tribes lists constituted in the Ministry for their recommendations etc.

(d) The Scheduled Tribes are specified under the Provision of Article 342 of the Constitution which envisage consultation with the concerned State Government regarding the fulfilment of the prescribed criteria by the concerned community. Further any amendment in the existing List of Scheduled Tribes can only be made through an Act of Parliament.

Statement

Inclusion of castes in the list of ST in U.P.

S.No.	Name of Organisation who has poposed inclusion in ST list during the last five years	Name of community recommended for inclusion in ST list
1	2	3
1	Gurdwara Shri Guru Singh Sabha, Naintal, U.P.	RAISIKH
2	Bhartiya Jogi Samaj Vikas Manch, U.P.	JOGI
3	Anusuchit Jati, Janjati and Pichra Varg Sanukt Parishad, Gorakhpur, U.P.	KHARWAR